



व्यापक डेटा संरक्षण कानूनों की आवश्यकता

यह एडिटरियल 01/06/2023 को 'हट्टि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित [“Ignore GDPR at your own peril”](#) लेख पर आधारित है। इसमें वैश्विक स्तर पर और भारत में डेटा संरक्षण कानूनों की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलम्भः

[सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन](#), [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधियक](#), [IT अधिनियम](#)।

मेन्सः

भारत का डिजिटल डेटा गवर्नेंस, इसकी चुनौतियाँ और आगे की राह

डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा का व्यापक संग्रहण एवं प्रसंस्करण डिजिटल पारस्थितिकी तंत्र के अंदर संचार एवं लेनदेन का आधार बन गया है। हालाँकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग की संभावना ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के संबंध में चर्चाओं को भी जन्म दिया है। **यूरोपीय संघ (EU) का सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन (General Data Protection Regulation- GDPR)**, **प्रभावी डेटा सुरक्षा ढाँचे का एक प्रमुख उदाहरण है।**

भारत भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधियक (Digital Personal Data Protection Bill), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act- IT Act) जैसी पहलों के माध्यम से अपने डेटा संबंधी शासन (Data Governance) को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। भारत में डिजिटल इंडिया अधिनियम के द्वारा आईटी अधिनियम, 2000 को प्रतस्थापित करना भी प्रस्तावित है।

डेटा शासन के संबंध में वैश्विक वनियमनः

■ यूरोपीय संघ (EU) का सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन (GDPR):

- **GDPR** व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु एक **व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित** है।
- यूरोपीय संघ में **नजिता या गोपनीयता का अधिकार (right to privacy) मौलिक अधिकार** के रूप में स्थापित है, जो व्यक्तिकी गरमि और उसके द्वारा सृजित डेटा पर उसके अधिकार का संरक्षण करने पर लक्षित है।
- GDPR द्वारा लगाए गए **जुरमाना या अर्थदंड ने विश्व भर के संगठनों को इस संबंध में अनुपालन को प्राथमिकता देने** के लिये प्रेरित किया है। इस क्रम में गूगल, व्हाट्सएप, ब्रिटिश एयरवेज़ और मैरियट सहित कई बड़ी कंपनियों पर पर्याप्त जुरमाना लगाया गया है।
- इसके अलावा **तीसरे विश्व के देशों पर डेटा ट्रांसफर के संबंध में GDPR के सख्त मानदंडों के कारण यूरोपीय संघ से परे भी डेटा सुरक्षा ढाँचे का प्रभाव पड़ा है।**

■ संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा शासनः

- अमेरिका में **नजिता के अधिकारों या सदिधांतों का कोई व्यापक सेट मौजूद नहीं है** जो यूरोपीय संघ के GDPR की तरह डेटा के उपयोग, संग्रहण एवं प्रकटीकरण को संबोधित करता हो।
- इसके बजाय यहाँ **सीमित स्तर पर क्षेत्र-वशिष्ट वनियमन मौजूद हैं।** इसके साथ ही डेटा सुरक्षा के संबंध में सार्वजनिक और नजि क्षेत्रों के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है।
 - यहाँ व्यक्तिगत सूचना के संबंध में सरकार की गतिविधियों एवं शक्तियों को अच्छी तरह से परभाषित किया गया है और **इन्हें नजिता अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम जैसे व्यापक कानूनों द्वारा संबोधित** किया गया है।
 - इसके साथ ही नजि क्षेत्र के लिये **कुछ क्षेत्र-वशिष्ट मानदंड तय** किये गए हैं।

■ चीन में डेटा शासनः

- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा** पर पछिले 2 वर्षों में जारी किये गए चीन के नवीन कानूनों में **व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (Personal Information Protection Law- PIPL)** शामिल है, जो नवंबर 2021 में लागू हुआ था।
 - इससे **चीन में डेटा सदिधांतों (data principals) से संबंधित विशेष अधिकार** प्राप्त हुए हैं जिससे व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया है।
- सितंबर 2021 में लागू हुए **डेटा सुरक्षा कानून (Data Security Law- DSL)** द्वारा व्यावसायिक डेटा के महत्त्व के स्तरों के आधार पर **डेटा को वर्गीकृत करना** आवश्यक बनाया गया है तथा सीमा-पार स्थानांतरण पर नए प्रतिबंध लागू किये गए हैं।

भारत में डेटा शासन से संबंधित प्रावधान

- **आईटी संशोधन अधिनियम, 2008:**
 - आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत भारत में कुछ गोपनीयता संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
 - हालाँकि ये प्रावधान व्यापक रूप से कुछ स्थितियों के लिये वशिष्ट हैं, जैसे **कमीडिया मंचों पर कशिरों और बलात्कार पीड़ितों के नाम प्रकाशित करने पर प्रतबंध आरोपित करना।**
- **जस्टिस के.एस. पुट्टासवामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, 2017:**
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से नरिणय दया कि भारतीयों को **संवैधानिक रूप से संरक्षित** नजिता का मौलिक अधिकार प्राप्त है जो **अनुच्छेद 21** में उपबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अंतरनहित अंग है।
- **बी.एन. श्रीकृष्ण समिति 2017:**
 - सरकार ने अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी, जिसने जुलाई 2018 में डेटा संरक्षण वधियक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
 - इस रिपोर्ट में भारत में नजिता कानून को सुदृढ़ करने के लिये अनुशंसाओं की एक वसितृत शृंखला प्रस्तुत की गई थी, जिसमें डेटा के प्रसंस्करण एवं संग्रहण पर प्रतबंध लगाना, डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना, **भूल जाने का अधिकार (right to be forgotten), डेटा स्थानीयकरण** आदि पहलुओं को शामिल किया गया था।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नयिम, 2021:**
 - **आईटी नयिम (2021)** के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के संबंध में वृहत तत्परता रखने हेतु बाध्य किया गया है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक (Digital Personal Data Protection Bill):**
 - यह वधियक भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर ऐसी स्थिति में लागू होगा जहाँ इस तरह के डेटा को ऑनलाइन एकत्र किया जाता है अथवा ऑफलाइन एकत्र कर डिजिटलाइज़ किया जाता है। यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या भारतीय व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग पर लक्षित हो।
 - इसके तहत व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिये प्रसंस्करण/संसाधित किया जा सकता है जिसके लिये व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो। कुछ मामलों में माना जा सकता है कि सहमति प्राप्त है।
 - डेटा फडियुशरी (Data fiduciaries) डेटा की परशुद्धता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा की समाप्ति करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
 - 'डेटा फडियुशरी' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मलिकर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है।
 - यह वधियक व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसमें सूचना प्राप्त करने, सूचना में सुधार करने एवं इसे मटाने की मांग करने और शकियात नवारण के अधिकार शामिल हैं।
 - केंद्र सरकार राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे नरिदष्टि आधारों के हित में वधियक के प्रावधानों के अनुप्रयोग से सरकारी एजेंसियों को छूट दे सकती है।
 - केंद्र सरकार वधियक के प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में नरिणय लेने हेतु भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India) की स्थापना करेगी।
- **आईटी अधिनियम, 2000 को डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 से प्रस्थापित करने का प्रस्ताव:**
 - आईटी अधिनियम मूल रूप से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन की सुरक्षा करने और साइबर अपराध को परिभाषित करने के लिये डिज़ाइन किया गया था। यह वर्तमान में साइबर सुरक्षा परदृश्य की जटलिताओं से पर्याप्त रूप से नपिटने और डेटा गोपनीयता अधिकारों से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है।
 - नया 'डिजिटल इंडिया अधिनियम' अधिकि नवाचारी, अधिकि स्टार्ट-अप्स को सक्षम करने और साथ ही सुरक्षा, विश्वास एवं जवाबदेही के संदर्भ में भारत के नागरिकों की रक्षा करने के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने पर केंद्रित है।

भारत में डेटा शासन से संबद्ध चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त जागरूकता:**
 - भारत में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने की राह में प्राथमिक बाधाओं में से एक यह है कि डेटा सुरक्षा के महत्त्व और डेटा उल्लंघनों से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में व्यक्तियों एवं संगठनों के बीच समझ सीमिति है। नतीजतन, व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये आवश्यक सावधानी बरतने में कठिनाई हो सकती है।
- **प्रवर्तन तंत्र का कमज़ोर होना:**
 - भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित मौजूदा कानूनी ढाँचे के प्रवर्तन के लिये सुदृढ़ तंत्र का अभाव है। यह अभाव डेटा उल्लंघनों और डेटा सुरक्षा नयिमों का पालन न करने के संबंध में संगठनों को जवाबदेह ठहराना कठिन बना देता है।
- **मानकीकरण का अभाव:**
 - भारत में डेटा संरक्षण नयिमों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन में एक प्रमुख बाधा यह है कि विभिन्न संगठनों के बीच इस संबंध में मानकीकरण का अभाव है। डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में एकरूपता की कमी से इसके अनुपालन पर्याप्तों के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **संवेदनशील डेटा के लिये अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:**
 - भारत में मौजूदा डेटा सुरक्षा ढाँचा स्वास्थय डेटा एवं बायोमेट्रिक डेटा जैसे संवेदनशील डेटा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने में वफिल रहता है। चूँकि संगठनों द्वारा इस प्रकार के डेटा के संग्रहण में वृद्धि हो रही है इसीलिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी चिंता का वषिय है।

आगे की राह:

- **रोल मॉडल के रूप में सरकार:** एक डेटा फडियूशरी और प्रोसेसर के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार को चाहिये कडिटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने के संदर्भ में रोल मॉडल के रूप में कार्य करे।
- प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के क्रम में संसदीय या न्यायिक निरीक्षण के साथ एकसर्वतंत्र एवं सशक्त डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कथिा जाना महत्त्वपूर्ण है।
- इस संदर्भ में नवाचार और वनियमन को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। व्यक्तगत डेटा की सुरक्षा के लिये कड़े नियम आवश्यक हैं लेकिन अत्यधिक नरिदेशात्मक एवं प्रतर्बिधात्मक मानदंड नवाचार को रोक सकते हैं और सीमा-पार डेटा प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। व्यक्तगत डेटा की प्रभावी ढंग से रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिये सही संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
- एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण कानून डजिटल शासन के व्यापक ढाँचे का केवल एक पहलू है। **व्यापक वनियमन सुनिश्चित करने के लिये साइबर सुरक्षा, प्रतसिपरद्धा, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों पर भी ध्यान दथिा जाना चाहिये।** यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण, जसिमें उसने डेटा अधनियम, डजिटल सेवा अधनियम, डजिटल बाज़ार अधनियम और AI अधनियम जैसे अतरिक्त पहलुओं को भी शामिल कथिा है, हमारे लिये भी मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में सुदृढ़ डेटा शासन को लागू करने में वदियमान चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए देश में डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिये आवश्यक रणनीतियों का सुझाव दीजथि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत के संवधिन के कसि अनुच्छेद के तहत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 29

उत्तर:C

व्याख्या:

- 'पुट्टासवामी बनाम भारत संघ' (वर्ष 2017) मामले में नजिता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित कथिा गया था।
- नजिता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संवधिन के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हसिसे के रूप में संरक्षित कथिा गया है।
- नजिता व्यक्तगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को नरिंत्रित करने की क्षमता को पहचानती है। नजिता पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इसे कोई भी अतिक्रमण वैधता, आवश्यकता और अनुपातिकता पर आधारित होना चाहिये।

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन और व्यक्तगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित कथिा जाता है। भारत के संवधिन में नमिनलिखित में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अरथित होता है? (2018)

- अनुच्छेद 14 और संवधिन के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीतिके नदिशक सदिधांत।
- अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 24 और संवधिन के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) की नौ न्यायाधीशों की बेंच ने अपने फैसले में न्यायमूर्तिके.एस. पुट्टासवामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मता से पुष्टि की कि नजिता का अधिकार भारतीय संवधिन के तहत एक मौलिक अधिकार है।।
- SC की बेंच ने कहा कि नजिता एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह संवधिन के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान कथिा गए जीवन एवं व्यक्तगत स्वतंत्रता की गारंटी में अंतरनहित है।
- पीठ ने यह भी कहा कि संवधिन के भाग III में नहिति मौलिक अधिकारों द्वारा मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत स्वतंत्रता एवं गरमा के अन्य पहलुओं से अलग-अलग संदर्भों में नजिता के तत्त्व भी उत्पन्न होते हैं।

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

?????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के वसितार का परीक्षण कीजयि । (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/need-for-comprehensive-data-protection-laws>

